सर्वहारा दृष्टिकोण

सोशलिस्ट यूनिटी सेन्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) का मुखपत्र (पाक्षिक)

वर्ष-30 अंक-5 7 से 21 मार्च, 2015 मुख्य संपादक कॉमरेड कृष्ण चक्रवर्ती Email: sarvaharadrishtikon@gmail.com मूल्य : 1 रुपये

विश्व सर्वहारा के महान नेता कार्ल मार्क्स की याद में

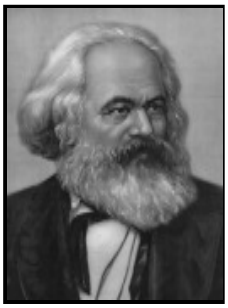

5 मई, 1818 - 14 मार्च, 1883

''अपने उत्पादों के लिए निरन्तर विस्तारमान बाज़ार की ज़रूरत बुर्जुआ वर्ग का दुनिया भर में पीछा करती है।... विश्व बाज़ार का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल कर बुर्जुआ वर्ग ने उत्पादन और उपभोग को हर देश में सार्वभौमिक स्वरूप दे दिया है।...उसने आबादी को संकुचित कर दिया है, उत्पादन के साधनों को केन्द्रीकृत कर दिया है और सम्पत्ति को चंद लोगों के हाथों में संकेन्द्रित कर दिया है। इसका अनिवार्य परिणाम राजनैतिक केन्द्रीकरण था।...यहां पर वाणिज्यिक संकटों का उल्लेख काफी है, जो अपने नियतकालिक आवर्तन द्वारा समस्त बुर्जुआ समाज के अस्तित्व को हर बार अधिकाधिक सख्त ढंग से आजमाते हैं,...और बुर्जुआ वर्ग इन संकटों पर किस प्रकार पार पाता है? एक ओर, उत्पादक शक्तियों को पूरी-पूरी संहति के बलात विनाश द्वारा और दूसरी ओर, नये-नये बाज़ारों पर कब्ज़े द्वारा और साथ ही पुराने बाज़ारों के और भी पूर्णतर दोहन द्वारा।''

–कार्ल मार्क्स-एंगेल्स (कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र)

विश्व सर्वहारा के महान नेता स्टालिन की याद में

21 दिसम्बर, 1879 - 5 मार्च, 1953

''जब मजदूरों के नेता कूटनीतिक खेल की दलदल में डूब जाते हैं, जब उनके शब्दों को उनके कृत्यों से समर्थन नहीं होता है, जब नेताओं की कथनी और करनी मेल नहीं खाती है, तो मजदूर अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कर पाते। रूस के मजदूरों ने कॉमरेड लेनिन में ऐसा असीम विश्वास क्यों प्रकट किया है? क्या महज इसलिए कि उनकी नीतियां सही थी? नहीं, अकेले इसी वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कि लेनिन की कथनी और करनी में कोई विरोधाभास नहीं था, क्योंकि वे जानते थे : 'लेनिन हमें बेवकूफ नहीं बनाते हैं!'

''अन्य बातों के साथ-साथ, यही वह बात थी जिस पर लेनिन की अॅथोरिटी टिकी हुई थी। इसी तरह से लेनिन ने मजदूरों को प्रशिक्षित किया था, इसी तरह से उन्होंने नेताओं पर विश्वास को उनमें जिन्दा रखा था।''– **जे वी स्टालिन**

केन्द्रीय बजट 2015 को पूँजीपतिपरस्त, अमीरपरस्त और जनविरोधी बताते हुए एस.यू.सी.आई.(सी) ने की निन्दा

एस.यू.सी.आई.(सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने केन्द्रीय बजट 2015 पर अपनी त्वरित प्रतिक्रिया देतें हुए 28 फरवरी को कहा कि जब देश के लोग बेतहाशा बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, बढ़ती रोजगार हानि, भयंकर गरीबी और कंगाली, मात्र जिन्दा रहने के न्यूनतम साधनों तक की अनुपलब्धता, बेकाबू भ्रष्टाचार और भूख तथा भुखमरी की वजह से मर रहे हैं उनके खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ा जा रहा है तब बीजेपी सरकार के वित्त मंत्री ने जाहिरा तौर पर अबोधगम्य आर्थिक जुमलों की झड़ी लगाते हुए धूर्ततम जनोत्तेजक भाषण के साथ एक बजट प्रस्तुत किया जिसमें सदैव के खोखले वायदों की प्रचुरता के अलावा प्रोग्रामों की घोषणाओं की भरमार है जिनमें से अधिकतर नई बोतल में पुरानी शराब हैं जो परम्परागत तौर पर कागजों में ही रहते हैं और गरीबों व वंचितों के लिए हमेशा की तरह घड़ियाली आंसू बहाते हुए पूरी तरह से एकाधिकारी पूँजीपतियों, औद्योगिक घरानों और कोरपोरेट सेक्टर के निहित वर्ग स्वार्थ की सेवा पर लक्षित हैं। उग्र सुधारवादी का जामा पहन कर उन्होंने यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास किया है कि निजी निवेश, आधारभूत ढाँचे के विकास, मैनुफैक्चरिंग इण्डस्ट्री, स्टॉक मार्किट ऑपरेशनों और पेंशन तथा बीमा ऐसे क्षेत्रों जिनमें भारी मात्रा में एफडीआई आने की अपेक्षा है पर अधिक जोर देने के जरिए सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क को विस्तारित करने के नाम पर पूँजीपति मालिकों के लिए निरन्तर अधिकतक मुनाफा कमाने का इंतजाम किया है जिसमें टैक्स छूटें, ऋण सुविधा और शुल्क माफी शामिल हैं। निजी पूँजीपतियों को ढेर सारी सुविधाएं प्रदान करके निवेश को प्रोत्साहित करने के माध्यम से रोजगार पैदा करने का छलावा भी पिछले सालों की तरह इस बजट में प्रकट हुआ है। नग्नता से उन्होंने कोरपोरेट टैक्स 30 से घटा कर 25% कर दिया है जबकि व्यक्तिगत टैक्स स्लैब को ज्यों का त्यों रखा है।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ राज्य स्तरीय जोरदार विरोध प्रदर्शन

रोहतक में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करते मजदूर-किसान, छात्र-नौजवान व महिलाएं

रोहतक: भूमि अधिग्रहण के काले अध्यादेश समेत भाजपा सरकार की पूँजीपतिपरस्त, जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) ने 28 फरवरी को रोहतक शहर में राज्य स्तरीय जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के आह्वान पर राज्य भर से महिलाओं समेत हजारों मजदूर, किसान, छात्र, युवा हुडा कॉम्पलैक्स में इकट्ठे हुए और शहर के प्रमुख चौराहों से होते हुए लघु-सचिवालय पहुँच कर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम 22 सूत्री मांगों का एक ज्ञापन उपायुक्त रोहतक की मार्फत दिया। विरोध प्रदर्शन की अगुआई एस.यू.सी.आई.(सी) की केन्द्रीय कमेटी के सदस्य एवं हरियाणा राज्य

(शेष पृष्ठ 2 पर)

केन्द्रीय बजट 2015 ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

सम्पत्ति कर समाप्त कर दिया है। सेवा कर जिसे सीधे-सीधे उपभोक्ताओं से चीजों के दाम बढ़ा कर वसूला जाता है उसे 12.36% से बढ़ा कर 14% कर दिया गया है। अनुत्पादक रक्षा बजट 2,46,727 करोड़ रुपए तक बढ़ा दिया गया है। काला धन उजागर करने और पैदा होने को भी वित्तमंत्री ने पूरी तरह मजाक बना कर रख दिया जब उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि तमाम ऐसे अघोषित धन रखने वालों और कर चोरी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन इस देश में एक बच्चा भी जानता है कि ये बड़े एकाधिकारी पूँजीपति, पहुँचवाले कारपोरेट, बेईमान राजनीतिज्ञ और भ्रष्ट अफसरशाह ही हैं जो काले धन पर फलते-फूलते हैं और इसलिए सरकार की यह तथाकथित आक्रामकता जिसे शासक एंकाधिकारी पूँजीपतियों ने मदद दे कर सत्ता में बैठाया है सिर्फ दिखावेबाजी के सिवाए और कुछ नहीं है। जरूरतमंदों को अनुदान के सीधे हस्तांतरण पर तथाकथित जोर भी एक और छलावा है क्योंकि डिलिवरी तंत्र भी अनेक कमी-खामियों से भरा पड़ा है और प्राप्ति न होने की दशा में क्षतिपूर्ति का कोई प्रावधान नहीं है।

देश के लोगों को वित्तमंत्री द्वारा अपने बजट भाषण में कहे गए चाशनी चढ़े चालाकी पूर्ण शब्दों के झांसे में नहीं आना चाहिए बल्कि सजावट के साथ पेश किए गए झांसों और भ्रमों को समझना चाहिए और इसलिए इस नितांत पूँजीपतिपरस्त, अमीर-परस्त बजट के खिलाफ प्रतिवाद में उठ खड़ा होना चाहिए।

जौनपुर, उ.प्र. में वामपंथी पार्टियों द्वारा रैली एवं सभा

जौनपुर में एसयूसीआई(सी), सीपीआई, सीपीआई(एम.), आरएसपी, फारवर्ड ब्लॉक, सीपीआई एमएल-लिबरेशन वामपंथी दलों को लेकर गठित संयुक्त संघर्ष समिति जौनपुर के बैनर तले 10 फरवरी को जिलाधिकारी जौनपुर के समक्ष एक विशाल रैली एवं सभा का आयोजन किया गया।

पॉलिटैक्निक चौराहे से शुरू की गई रैली में सैकड़ों छात्र-युवा, महिलाएं व किसान-मजदूर शामिल हुए। मांग पट्टिकाओं व लाल झण्डों-बैनरों से सुसज्जित रैली रूहट्टा, ओलन्दगंज होते हुए कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच कर सभा में तब्दील हो गई। इस दौरान, महंगाई, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ। मनरेगा में कटौती बन्द करो, एफडीआई व पीपीपी नीति रद्द करो, काला धन वापस लाओ, शिक्षा व सार्वजनिक संस्थानों में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं साम्प्रदायिकता के वाहक तत्वों की घुसपैठ बन्द करो, लव जेहाद, धर्मान्तरण, घर वापसी के नाम पर नफरत फैलाना बन्द करो; अल्पसंख्यकों, दलितों व महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करो, इत्यादि मांगों सम्बन्धित नारे लगाए गए।

अध्यक्षमण्डली में शामिल वामदलों के कॉ. जगदीशचन्द्र अस्थाना, कल्पनाथ गुप्त, किरन शंकर सिंह, गोपालमणि त्रिपाठी ने सभा की अध्यक्षता की। संचालन सुभाष चन्द्र पटेल ने किया। सभा के शुरू में कॉ. दिलीप कुमार ने क्रान्तिकारी गीत प्रस्तुत किया। इसके बाद एसयूसीआई(सी) से कॉ. प्रमोद कुमार शुक्ल, रविशंकर मौर्य, महेन्द्रनाथ मौर्य, राजेन्द्र तिवारी; सीपीआई से कॉ. जयप्रकाश सिह, उदल यादव, सुभाष सरोज; सीपीआई(एम) से विजयप्रताप सिंह, जयालाल सरोज, इंद्रजीत पाल, नीरज श्रीवास्तव व आर.एस.पी. से गोपालमणि त्रिपाठी ने सभा को सम्बोधित किया। अन्त में जिलाधिकारी जौनपुर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को सम्बोधित 9सूत्री मांगपत्रक सौंपा गया।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश ...

(पृष्ठ 1 का शेष)

कमेटी के सचिव कॉमरेड सत्यवान, राज्य कमेटी के वरिष्ठ सदस्य कॉ. अनूप सिंह मातनहेल, राजेन्द्र सिंह(रेवाड़ी), रामफल(भिवानी), ईश्वर सिंह राठी(सोनीपत), रोशनलाल(कैथल), हरिप्रकाश व विजय कुमार ने की।

हुडा काम्पलैक्स में प्रदर्शनकारियों को सम्बोधित करते हुए किसान नेता अनूपसिंह मातनहेल ने कहा कि भूमि अधिग्रहण के काले अध्यादेश को मोदी सरकार ने यदि रद्द नहीं किया और किसान-खेतमजदूरों व पशुपालकों के पुश्तैनी रोजगार के एकमात्र साधन कृषि भूमि को जबरन अधिग्रहण करने की कोशिश की गई तो हर जगह नन्दीग्राम की तर्ज पर जुझारू आन्दोलन होंगे। उन्होंने कहा कि देश के बड़े पूँजीपति घरानों की गिद्ध-दृष्टि कृषि भूमि पर लगी है। उन्हीं के स्वार्थ में मोदी सरकार ने यह काला अध्यादेश जारी किया है। देश भर के किसानों के जोरदार संघर्षों के दबाव में अंग्रेजों के कानून को बदल कर 2013 में नया भूमि अधिग्रहण कानून बना था। इसमें किसानों की सहमति लेने, बाजार भाव से जमीन का मुआवजा देने, सामाजिक व पर्यावरणीय प्रभाव और खाद्य-उत्पादन के आंकलन का प्रावधान था। भूमि के बदले भूमि देने व वैकल्पिक रोजगार व आर्थिक सहायता देने जैसे प्रावधान भी थे। मोदी सरकार ने बड़ी पूँजी के स्वार्थ में इन प्रावधानों को एक ही झटके में खत्म कर दिया। किसान-खेत मजदूर इसे कतई स्वीकार नहीं करेंगे। अनूपसिंह ने फसलों के लाभकारी दाम देने की मांग को भी जोरदार ढंग से उठाया।

कॉ. राजेन्द्र सिंह ने कहा कि भाजपा शासन में 'अच्छे दिन' केवल पूँजीपतियों के आए हैं। 'सबका साथ सबका विकास' के नारे को भाजपा भूल गई। विदेशी पूँजीपतियों का साथ लेकर देशी पूँजीपतियों की सेवादार बन गई है। उन्होंने महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, अशिक्षा, बीमारी व कुपोषण और महिलाओं पर किए जा रहे अत्याचार, रेप, गैंगरेप, हत्याओं पर कारगर रोक लगाने की मांग की।

राज्य कमेटी के अन्य सदस्य कॉ. रामफल ने मोदी सरकार द्वारा 108 जीवन रक्षक दवाओं के दाम बढ़ाने, श्रम अधिकारों में कटौती किये जाने, बैंक, जीवन बीमा, रेल, रक्षा क्षेत्र में 49 से 100 प्रतिशत एफ.डी.आई. की इजाजत दिये जाने की कड़ी निन्दा की। उन्होंने सभी श्रमिकों और आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों चौकीदारों, कच्चे कर्मचारियों को 15000 रुपये मासिक न्यूनतम वेतन देने की मांग पूरी न करने पर गहरा रोष प्रकट किया। भवन निर्माण मजदूर-कारीगरों का बिल्डरों व ठेकेदारों द्वारा किए जा रहे शोषण का उन्होंने कड़ा विरोध किया।

पार्टी नेता कॉ. सत्यवान ने भाजपा द्वारा शिक्षा प्रणाली में दकियानूसी, पोंगापंथी, सामंती संस्कृति थोपने का कड़ा विरोध किया और प्रदेश में वैज्ञानिक, धर्मनिरपेक्ष व जनतांत्रिक शिक्षा पद्धति लागू कराने और युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित कराने के लिए जोरदार आन्दोलन की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने घोषणा की कि एसयूसीआई (कम्युनिस्ट) भूमि अधिग्रहण के काले अध्यादेश के खिलाफ प्रदेशव्यापी अभियान चलाएगी।

भाजपा के रेल बजट व आम बजट को उन्होंने पूँजीपतिपरस्त व जनविरोधी बताया।

ज्ञापन में मांग की गई : भूमि अधिग्रहण का काला अध्यादेश रद्द करो। कृषि भूमि के अधिग्रहण पर पूर्ण रोक लगाओ। रद्द हुए सेज की अधिग्रहित जमीन किसानों को वापस दो। महंगाई, बेराजगारी पर रोक लगाओ। सब को सस्ता राशन व रोजगार दो। महिलाओं पर किए जा रहे अन्याय, अत्याचार, रेप, गैंगरेप व हत्याओं पर कड़ी रोक लगाओ। डीजल व पेट्रोल के रेट आधे करो। इन पर लगाया वैट हरियाणा सरकार रद्द करे। बस भाड़ा, रेल भाड़ा घटाओ व बिजली सस्ती करो। टोल टैक्स हटाओ। रेल, कोयला, बीमा, बैंक व रक्षा मामलों में 49 से 100 प्रतिशत एफडीआई रद्द करो। 108 जीवन रक्षक दवाओं के बढ़ाए गए दाम वापस लो। श्रम अधिकारों में कटौती करना बन्द करो। 15 हजार महीना न्यूनतम वेतन लागू करो। किसानों की फसलों के लाभकारी दाम दो। बोनस पर लगाई रोक हटाओ। समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद मुकम्मल हो। कृषि और राशन वितरण प्रणाली में सब्सीडी बढ़ाओ। गाँवों की बणी-जंगलात भूमि को किसी दूसरे काम के लिए देने या न देने का अधिकार वापस ग्राम सभा को दो। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोडवेज, बिजली, पानी को मुनाफा लूटने की चीज बनाना बन्द करो। भवन निर्माण मजदूर-कारीगरों के रजिस्ट्रेशन व सामाजिक सुरक्षा लाभ पाने की प्रक्रिया सरल करो। हर जिला में मजदूर कल्याण बोर्ड के दफ्तर खोलो व पर्याप्त स्टाफ लगाओ। आशा, मिड डे मील, आंगनवाड़ी आदि स्कीम वर्करों, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों, चौकीदारों व कच्चे कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दो, तब तक उन्हें 15 हजार रुपए महीना न्यूनतम वेतन दो। शिक्षा के निजीकरण-व्यापारीकरण व भगवाकरण पर रोक लगाओ। बजट में केन्द्र का 10% प्रतिशत व प्रदेश का कम से कम 20% शिक्षा पर खर्च किया जाए। सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से पास-फेल की वार्षिक परीक्षा प्रणाली और 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को फिर से बहाल किया जाए। शिक्षा सलाहकार समीति, विश्वविद्यालयों के कुलपतियों व अन्य संवैधानिक पदों पर केवल उच्चकोटि के योग्य व्यक्ति ही नियुक्त हों और उनकी चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो। यूरिया को सरकारी नियंत्रण में वापस लो। कोपरेटिव सोसायटी के जरिए इसकी पर्याप्त मात्रा में सप्लाई दो। गरीब किसानों के कर्जे खत्म करो। 1% ब्याज दर पर उन्हें पर्याप्त कर्ज दो। बैंकों द्वारा कर्जवान किसानों की जमीन की कुर्की पर पूर्ण रोक लगाओ। आवारा पशुओं से फसलों व लोगों की जान-माल को हो रहे भारी नुकसान से बचाने के पुख्ता इन्तजाम करो। मनरेगा स्कीम में कटौती बन्द करो। खेत मजदूरों का पंजीकरण करो। बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन व विक्लांग भत्ता 4000 रुपये महीना लागू करो।

देश भर में श्रमिकों ने मोदी सरकार की श्रमिक – विरोधी नीतियों के प्रतिरोध में किया सत्याग्रह

26 फरवरी को पूरे देश भर में मोदी सरकार के श्रमिक-विरोधी रवैए को लेकर कई लाख मजदूरों ने सत्याग्रह/प्रदर्शन/धरना के जरिए से प्रतिरोध में हिस्सा लिया। वे मजदूर-विरोधी श्रम कानून परिवर्तन, सार्वजनिक क्षेत्र में लगातार विनिवेश की नीति, डिफेंस, इंश्योरेंस, रेलवे आदि में ''विदेशी पूँजी'' को अंधाधुंध न्यौता दिये जाने के विरोध में तथा श्रमिकों को न्यूनतम वेतन 15 हजार मासिक देने की, ठेकेदारी प्रथा की समाप्ति व समान काम के समान वेतन की, सबको पेंशन, सबको सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान करने की, बोनस, पीएफ आदि देने की और ग्रेच्युटी पर सीमा समाप्त करने की मांगें उठा रहे थे।

दिल्ली : इसी कड़ी में दिल्ली के श्रमिक संगठनों ने केन्द्रीय व राज्य नेतृत्व में संसद मार्ग पर प्रदर्शन व सत्याग्रह किया। उनकी मांग है कि श्रम कानून सुधार को वापस किया जाए, विनिवेश पर रोक लगाई जाए।

इनका नेतृत्व बीएमएस के बैजनाथ राय व नागेन्द्र, इण्टक से एम राघवैया व राजू, एटक से जी एल धर, अमरजीत कौर, डी एल सचदेव, धीरेन्द्र शर्मा, विद्यासागर गिरी, सीटू से तपन सेन सांसद व मनकोटिया, एक्टू से संतोष राय, एआईयूटीयूसी से आर. के. शर्मा, एचएमएस, यूटीयूसी व मैक के लीडर आदि कर रहे थे। एआईबीईए के जे.पी. शर्मा व एआईबीओए के एस.एस.सिसौदिया भी मौजूद थे।

वक्ताओं ने मोदी सरकार पर अरोप लगाया कि वह श्रमिक संगठनों की अनदेखी करते हुए एकतरफा मजदूर-विरोधी कानून संशोधनों को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री दफ्तर से पत्र के जरिए राज्य सरकारों को कहा गया है कि वे राजस्थान सरकार द्वारा किए गये श्रम संशोधनों के रास्ते पर चलें। उनकी गुजरात सरकार द्वारा श्रमिकों के हड़ताल के अधिकार पर प्रतिबंध, औद्योगिक विवाद शुरू करने की मियाद घटाने, विशेष औद्योगिक क्षेत्रों को बिना जवाबदेही के मजदूरों को काम से निकालने जैसे संशोधनों की कड़ी निन्दा की गई।

मजदूर नेताओं का कहना था कि 5 दिसम्बर के राष्ट्रव्यापी प्रतिरोध के बाद भी सरकार ने श्रमिक संगठनों के आक्षेप पर विचार नहीं किया इसलिए यह राष्ट्र स्तरीय सत्याग्रह आयोजन किया गया है। मजदूर संगठन संयुक्त तौर पर अपने आन्दोलन को आने वाले दिनों में और भी तीव्र करेंगे।

हरियाणा : बीजेपी की केन्द्र व राज्य सरकारों द्वारा श्रमकानूनों में पूंजीपतिपरस्त संशोधनों के खिलाफ अपने रोष का इजहार करते हुए हरियाणा में सभी जिलों में ट्रेड यूनियनों के संयुक्त बैनर तले जेल भरो कार्यक्रम लिया गया। सोनीपत में पंचायत भवन से शुरू करके छोटूराम चौक होते हुए उपायुक्त कार्यालय तक जुलूस निकाला गया। इसका नेतृत्व सीआईटीयू के आनन्द शर्मा, एआईयूटीयूसी के ईश्वर सिंह राठी, इन्टक के रणबीर सिंह बूरा, बीएमएस के बहादुर यादव, एटक के हंसराज राणा, बैंक एम्पलाइज फैडरेशन के एनपी मुंझाल, कर्मचारी महासंघ के राजेन्द्र राठी, एसकेएस के राममेहर शर्मा और संयुक्त कर्मचारी मंच के आर के नागर ने किया और हजारों मजदूर-कर्मचारियों ने गिरफ्तारियाँ दी। भिवानी में नेहरू पार्क में ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर मजदूर-कर्मचारी एकत्रित हुए। सीटू नेता विनोद, एआईयूटीयूसी नेता रामफल, बीएमएस से मदन कौशिक, इन्टक से राम अवतार, सर्वकर्मचारी संघ से जय प्रकाश परमार, महासंघ से राजीव मंदोला की संयुक्त अध्यक्षता में सभा हुई। वहाँ से जुलूस शुरू हुआ और हांसी गेट, पुराना बस अड्डा होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचा और गिरफ्तारियाँ देने के लिए बसों में बैठ गये, लेकिन बस चालकों ने प्रदर्शनकारियों का समर्थन करते हुए हड़ताल कर दी ड्युटी मजिस्ट्रेट ने 2070 मजदूर-कर्मचारियों की गिरफ्तारियाँ दिखा कर छोड़ दिया गया।

अहमदाबाद : केन्द्र व गुजरात राज्य सरकार की मजदूर-विरोधी नीतियों के खिलाफ एआईयूटीयूसी सहित तमाम केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर इस दिन अहमदाबाद के लाल दरवाजा पर प्रदर्शन किया गया और मजदूर-कर्मचारियों ने गिरफ्तारियाँ दी।

अन्य विवरण फॉर्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन का स्थान	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशन की अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
प्रकाशक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005
सम्पादक का नाम	: सत्यवान
राष्ट्रीयता	: भारतीय
पता	: 3ए/38, डब्ल्यू.ई.ए. करोल बाग, नई दिल्ली-110005

उन व्यक्तियों के नाम एवं पते जो अखबार के स्वामी है या जो कुल पूँजी के एक प्रतिशत या उससे अधिक के हिस्सेदार हैं

मैं सत्यवान, एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दिए गए उपरोक्त विवरण मेरी पूरी जानकारी एवं विश्वास के आधार पर सत्य है।

ह. सत्यवान
प्रकाशक के हस्ताक्षर

दिनांक : 5 मार्च, 2015

कॉ. गोविन्द पनसारे की मौत पर कॉमरेड प्रभाष घोष ने जताया गहरा शोक

महाराष्ट्र के वरिष्ठ वामपंथी नेता, अनेक वाम-जनवादी आन्दोलनों के अग्रणी सैनिक कॉमरेड गोविन्द पनसारे के हत्याकाण्ड पर गहरा शोक प्रकट करते हुए सीपीआई के महासचिव को 21 फरवरी को एसयूसीआई (सी) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने एक चिट्ठी दी।

गत 16 फरवरी को शोलापुर में अपने घरके पास कॉमरेड गोविन्द पनसारे (82) और उनकी पत्नि उमा पनसारे को बदमाशों ने गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में कॉमरेड पनसारे को पहले शहर के आस्टिर आध ार हस्पताल में, बाद में बगीच कैण्डी में भर्ती कराया गया। वहीं उन्होंने अन्तिम सांस ली। शोलापुर में रोड टोल टैक्स माफिया के हमले में ही वे मारे गये। क्योंकि उनके खिलाफ उन्होंने जोरदार प्रचार चला रखा था।

शोक संदेश में कॉमरेड प्रभाष घोष ने कहा कि निहित स्वार्थों के जनविरोधी कार्यकलापों के खिलाफ उन्होंने जनमत तैयार कर दिया था, इससे खतरा महसूस कर उन्होंने उनकी हत्या कर दी। उनकी मृत्यु से देश के वाम-जनवादी आन्दोलन ने एक निष्ठावान योद्धा खो दिया है। सीपीआई पार्टी के सदस्यों और कॉमरेड पनसारे के परिवार के सदस्यों के शोक में भागीदार होते हुए कॉमरेड प्रभाष घोष ने कातिलों को तुरंत गिरफ्तार करने और कठोर सजा देने की मांग की।

शहीद चंद्रशेखर आजाद को याद किया

वाराणसी : एआईडीवाईओ ने 27 फरवरी को शहीद उद्यान पार्क सिंगरा, वाराणसी में महान क्रान्तिकारी चन्द्रशेखर आजाद का शहादत दिवस सम्मानपूर्वक मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेन्द्र प्रसाद एवं संचालन कमलेश मौर्य ने किया। मुख्य वक्ता चन्द्रेश कुमार थे।

कानपुर : जन-प्रतिरोध आन्दोलन समिति, कानपुर द्वारा चन्द्रशेखर आजाद के 84वें शहादत दिवस पर उनको याद किया। जिला अध्यक्ष ब्रजेश सिंह कटियार, जिला सचिव अरविन्द अवस्थी, कमेटी सदस्य शाहीद सिद्दीकी, मान सिंह, रवीन्द्र कुमार गौतम, बालेन्द्र कटियार ने बात रखी।

सागर : एआईडीवाईओ व एआईडीएसओ ने चंद्रशेखर आजाद के शहादत दिवस पर तिली हाई स्कूल के पास सभा की जिसकों अध्यक्षता डी.वाई.ओ. के जिला अध्यक्ष अशोक कुशवाहा ने की।

सरायकेला-खरसवां : झारखण्ड राज्य के सरायकेला-खरसवां जिला स्थित आदित्यपुर में सरस्वती सदन पुस्तकालय एसएन हाई स्कूल, मध्य विद्यालय कुलपटांगा, राजकीय मध्य विद्यालय, पथ सं. 19 चौक आदित्यपुर कालोनी में अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत दिवस मर्यादा के साथ मनाया।

सूरत : गुजरात राज्य के सूरत शहर में ऑल इण्डिया डी.एस.ओ. की ओर से अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद का शहादत दिवस सम्मान के साथ मनाया। इस अवसर पर एक नाटक भी मंचित किया गया।

R.N.I. No.- 43022/85
P.R.No.-DL(C)-01/1123/2015-2017
Posting at IPMBC on 7–8 and 22–23 Fortnightly , Date of Printing : 5 March, 2015

रेल के सफर को जोखिमभरा, महंगा व असुरक्षित बनाने वाले मुद्दों को धता बताते हुए निजीकरण बढ़ाने की शातिराना चाल के रूप में पेश किये गये रेल बजट की एस.यू.सी.आई.(सी) ने की आलोचना

26 फरवरी 2015 को एसयूसीआई(सी) महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने निम्नलिखित बयान जारी किया:

बीजेपी रेलवे मंत्री ने रेलवे बजट प्रस्तुत करते हुए अति चालाकीपूर्ण ढंग से गंभीर मुद्दों को धता बता दी। जो रेलवे को सालों से आक्रांत कर रहे हैं जैसे गाड़ियों का देरी से चलना, कोचों और रेकों की खस्ता हालात, अस्वास्थ्यकर रख रखाव और रेल लाइनों की अनुपयुक्त देखभाल, चोरी, सेंधमारी की बढ़ती घटनाएं और महिला यात्रियों पर अत्याचार, ऑपरेशन के हर स्तर पर बेकाबू भ्रष्टाचार, अनाचार, भाई-भतीजावाद, गबन, लूट और चोरी में भयावह बढ़ोत्तरी, सुपरफास्ट चार्ज के रूप में पिछले दरवाजे से अतिरिक्त भाड़ा वसूली, तत्काल कोटे की संख्या में बढ़ोत्तरी और बार-बार होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या जिसने रेलवे यात्रा को महंगा, जोखिम भरा, परेशानी भरा और सबसे बढ़कर, असुरक्षित बना दिया है। इसके बजाए उन्होंने नीरस (रूटीन) वायदो की प्रचुरता के साथ परम्परागत घोषणाओं का लोक लुभावन रास्ता चुना विशेषकर आई टी सक्षम सुविधाओं की बहुतायत के साथ रेलवे को हाई टैक बनाने का दिखावा किया जिनके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये टैक्नोलॉजी के जानकार यात्रियों के एक छोटे से तबके तक ही सीमित रहेगा और इसीलिए साधारण यात्रियों की अधिकतर संख्या के लिए किसी काम का नहीं होगा। इस प्रकार मंत्री ने चालाकी से लोगों को उल्लू बनाने का प्रयास किया है और बजट प्रावधानों के मनहूस चेहरे को छिपाने की कोशिश की है।

मंत्री ने यात्री भाड़ा नहीं बढ़ाने का श्रेय भी लेना चाहा है जबकि सच्चाई यह है कि अब ऐसी बढोत्तरी को बजट में अंजाम नहीं दिया जाता है बल्कि संसद को दरकिनार करते हुए प्रशासनिक आदेश जारी करने के माध्यम से लोगों पर थोपा जाता है जैसा कि पिछले साल हुआ जब बीजेपी सरकार ने यात्री किराए में 14.2% और माल भाड़े में 6.5% की भारी वृद्धि की थी। इसके अलावा, अलग से रेलवे टैरिफ अथोरिटी को अधिकार दे दिया गया है कि वह जब जरूरी समझे किराए और सरचार्ज बढ़ा सकती है और संसद में इसे पास कराने की जरूरत नहीं होगी इसलिए रेलवे मंत्री को बजट में भाड़ा बढ़ाने की किसी घोषणा की जरूरत ही नहीं है। फिर भी कोयले, लौह अयस्क और स्टील पर माल भाड़ा। अप्रैल से बढ़ जाएगा जिसका निरंतर प्रभाव अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों पर पड़ेगा।

उल्लेखनीय बात यह है कि मंत्री ने अगले पाँच सालों में 8.5 लाख करोड़ रूपये के निवेश की संभावना व्यक्त की है और स्पष्ट संकेत दिया है कि इतने सारे संसाधन या तो बहुपक्षीय विकास बैंकों या पेंशन फण्डों से और ''पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप'' (पीपीपी) के आयाम को बढ़ाते हुए रेलवे के निजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के माध्यम से आएंगे। निश्चित ही निजी ऑपरेटर अपने निवेश पर अधिकतम मुनाफा लेंगे जिसके लिए वे समय-समय पर किराया और अन्य शुल्क भारी मात्रा में बढ़ाने के जरिए आम यात्रियों पर अधिकाधिक बोझ लादेंगे। उल्लेखनीय ढंग से, तमाम स्टेशनों को रख-रखाव के लिए निजी घरानों को सौंपा जाएगा। इससे उन स्टेशनों पर भी प्लेटफार्म टिकट लगा दिए जाएंगे जिन पर अभी जरूरत नहीं होती है और उन स्टेशनों पर प्लेटफार्म टिकटों के दाम बढ़ा दिए जाएंगे जहाँ जरूरत होती है। इसका उल्लेख भी जरूरी है कि पिछले साल सरकार ने कहा था कि किराए ढाँचे को ईंधन-तेल की कीमत से जोड़ा जाएगा मायना है कि यदि तेल की कीमतें कम होंगी तो किराए कम हो जाएंगे। लेकिन तेल कीमत में गिरावट के बावजूद किराए कम नहीं किए गए हैं जबकि निश्चित है कि यदि तेल के दाम बढ़े तो इसी तर्क की आड़ में किराए तुरन्त बढ़ा दिए जाएंगे। बजट भाषण के मधुर शब्दों के नितांत कपटपूर्ण छद्मावरण को समझने और बीजेपी सरकार की एकाधिकारी पूँजीपतिपरस्त कॉरपोरेटपरस्त जनविरोधी छलबाजी के खिलाफ हम इसके प्रतिवाद में उठ खड़े होने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं।

भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ चल रहे आन्दोलनों का एसयूसीआई(सी) ने किया जोरदार अभिनन्दन

मोदी सरकार द्वारा 29 दिसम्बर 2014 को पास किए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ चल रहे आन्दोलन के संदर्भ में सोशलिस्ट यूनिटी सेण्टर ऑफ इण्डिया (कम्युनिस्ट) के महासचिव कॉमरेड प्रभाष घोष ने 22 फरवरी 2015 को निम्नलिखित बयान जारी किया:

''ब्रिटिश औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून 1894 के खिलाफ लोगों में व्याप्त व्यापक अशान्ति और पश्चिम बंगाल व देश में अन्य जगहों पर नंदीग्राम एवं सिंगूर जैसे आन्दोलनों के दबाव में यूपीए सरकार भूमि अधिग्रहण कानून 2013 पास करने को मजबूर हुई थी। हालांकि जन आन्दोलनों की कुछ मांगों को कथित कानून में शामिल किया गया था जबकि ज्यादातर मांगों को इसके दायरे से बाहर ही रखा गया था। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधानों जैसे निजी प्रोजेक्टों के लिए अधिग्रहण से प्रभावित 80% किसानों और पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप (पीपीपी) प्रोजेक्टों के लिए 70% किसानों की सहमति; खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बहुफसली भूमि का अधिग्रहण न करने; ग्राम सभाओं की हिस्सेदारी के साथ प्रोजेक्टों के सामाजिक और पर्यावरणीय प्रभावों का आंकलन; सिर्फ प्राकृतिक आपदा के मामले में ही आपातकालीन धारा के इस्तेमाल को शामिल किया गया था। कानून में कुछ अन्य हितलाभ भी प्रदान किए गए थे जैसे आर्थिक मुआवजे को बढ़ाना वैकल्पिक रोजगार मुहैया कराना और प्रभावित लोगों को भूमि आवंटित करना तथा अधिग्रहण के बाद पांच या उससे अधिक वर्षों तक मालिकों द्वारा यदि भुगतान स्वीकार न किया जाए तो भूमि को वापिस कर देना।

मोदी सरकार द्वारा 29 दिसम्बर 2014 को लागू किए गए भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 ने भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के ऐसे तमाम प्रावधानों को छीन लिया है। जिसे पूर्ववर्ती यूपीए सरकार को जन आन्दोलन के दबाव में स्वीकार करना पड़ा था। अब निजी प्रोजेक्टों के लिए अधिग्रहण के मामले में भी किसानों की सहमति लेने की जरूरत नहीं रहेगी और साथ ही साथ उद्योग के लिए बहु फसली भूमि को अधिग्रहित करने का भी प्रावधान है। सभी तरह के अधिकारिक और पीपीपी के साथ साथ निजी हस्पतालों और स्कूलों जैसे संस्थानों के लिए कम्पनियों द्वारा भूमि अधिग्रहित की जा सकेगी। पूर्ववर्ती कानून के पूनर्वास और मुआवजे के प्रावधानों को बरकरार रखना वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं कर सकता है। और इस प्रकार यह भूमि के मालिक किसानों को धोखा देने के लिए सिर्फ एक झांसा है। भाजपा सरकार द्वारा अध्यादेश को लागू किया गया है। ताकि दोनों भारतीय और विदेशी उद्योगपति, कम्पनियाँ और बिल्डर्स औद्योगिक गलियारे निर्माण कर सकें, खदान खोल सकें और किसानों की जमीनें हड़प कर गरीबों के लिए सस्ते मकान बनाने के नाम पर भू सम्पत्ति मुनाफों का अम्बार लगा सकें।

हमारी पार्टी की केन्द्रीय कमेटी भूमि अधिग्रहण अध्यादेश 2014 के खिलाफ चल रहे आन्दोलन का अभिवादन करती है और लोगों से आह्वान करती है कि वे इस न्यायसंगत आन्दोलन के पक्ष में अपना भरपूर समर्थन दें। केन्द्रीय कमेटी का कहना है कि यदि मांग स्वीकार नहीं की जाती है और जमीनों को जबरदस्ती छीना जाता है तो सभी जगह नन्दीग्राम संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया जाना चाहिए।

पेट्रोल के दाम बढ़ाने का कड़ा विरोध

रोहतक : 13 फरवरी को एस.यू.सी.आई.(कम्युनिस्ट) पार्टी के हरियाणा राज्य सचिव कॉमरेड सत्यवान ने बीजेपी की खट्टर सरकार द्वारा पेट्रोल के दाम 2.5 रुपये प्रति लीटर बढ़ाये जाने का कड़ा विरोध किया है। प्रैस को जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया भर में जब कच्चे तेल के दाम लगातार घट रहे हैं तब खट्टर सरकार ने वैट में 5 प्रतिशत वृद्धि करके प्रदेश की जनता पर नाजायज आर्थिक बोझ डाल कर घोर जनविरोधी कृत्य किया है। उन्होंने इस वृद्धि को तत्काल रद्द करने की मांग की।

कॉ. सत्यवान ने कहा कि विश्व बाजार मे कच्चे तेल के दाम नीचे गिरने से पेट्रोल व डीजल के दाम 25-30 रु. लीटर होने चाहिए थे। परन्तु सरकार ने ऐसा न करके इसका सारा फायदा तेल कम्पनियों को पहुँचा दिया और उपभोक्ताओं पर नाजायज बोझ डालने से भी गुरेज नहीं किया। भाजपा सरकार की इस मनमानी का एसयूसीआई(सी) डट कर विरोध करेगी और प्रदेश भर में इसके खिलाफ जनआन्दोलन संगठित करेगी।

24 फरवरी को दिल्ली में जंतर मंतर पर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ हुए विशाल प्रदर्शन में ऑल इण्डिया कृषक खेतमजदूर संगठन का प्रतिनिधित्व एसयूसीआई(सी) के केन्द्रीय कमेटी सदस्य कॉ. सत्यवान ने किया। इसमें अन्ना हजारे व मेधा पाटकर भी शामिल थी

"Print-line
Printed and published by Com. Satyawan on behalf of the Central Committee of the Socialist Unity Centre of India (Communist) and printed at M/s Balaji Offset Printers, 315/21, Shahzada Bagh, Daya Basti, Delhi and published at 3A/38, WEA, Satnagar, Karol Bagh, New Delhi-110005. Editor: Com. Satyawan, Member, Central Committee, SUCI(C)."